अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जुलाई 2006 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रुपये

आई सी डी एस का
सर्वव्यापीकरण तथा नियमितिकरण करो !

मई दिवस

पूरे देश में इस वर्ष मई दिवस विशाल जमायत में मनाया गया। बहुत से ओद्यौगिक केंद्रों व कार्यस्थलों पर मई दिवस के शहीदों के बलिदान को याद कर जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक बैठकें इत्यादी कीं तथा साम्राज्यदादी ताकतों के विरूद्ध व जनता के जीवन एवं अधिकारो पर हो रहे हमलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता ली।

कोलकाताः पांच दौर में कराए गए विधान सभा चुनावों के बीच पड़े इस बार के मई दिवस को कोलकाता के मेहनतकशों ने खूब धूमधाम से मनाया। शहीद मीनार मैदान की एक विशाल सभा में बोलते हुए कामरेड ज्योति बसु ने हड़ताल के अधिकार को लेकर चल रही बहस को निरर्थक बताया और कहा कि मजदूर अगर इसे छोड़ देगा तो फिर उनकी मांगें कौन मानने वाला है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ट्रेड यूनियन आंदोलन से जोड़ने पर भी ज्योति बसु ने जोर दिया।

अरुणांचल : इटानगरः यहां श्रमिकों की एक विशाल जन सभा का आयोजन राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। इसका आयोजन ऑल अरुणांचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन (सीटू) की ओर से किया गया था। सीआइटीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा असम राज्य समिति के महासचिव कामरेड देबेन भट्टाचार्य के अलावा एएपीडब्ल्यूयू के अध्यक्ष जाली सोनम, अरुणांचल टाटा सूमो वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोइ टक्कर, अन्य स्थानीय नेताओं त्वांग, सेपा, टी के बग्गाना इत्यादि ने जन सभा को सम्बोधित किया।

असम (गुवाहाटी) : असम के सभी जिलों तथा चाय बगीचों में रैलियों का आयोजन किया गया। यहां के जज मैदान में श्रमिक संगठनों की ओर से एक संयुक्त सभा का आयोजन किया गया । कामरेड बिमल नांदी की ओर से लाल झण्डा फहराया गया।

त्रिपुरा : राज्य की राजधानी अगरतला सहित सभी नगरों में स्थान–स्थान पर लाल झण्डे फहराए गए। धर्मनगर, किलासहर तथा दूसरे स्थानों पर जन सभाएं आयोजित की गई।

पंजाब : लुधियाना में सीआइटीयू के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हीरो साइकिल लिमिटेड के गेट पर आयोजित जनसभा को सीआइटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड रघुनाथ सिंह ने सम्बोधित किया और लाल झण्डा फहराया। इसके अतिरिक्त रॉकमैन साइकिल इंडस्ट्रीज के गेट पर साइकिल श्रमिकों के नेता जतिन्दरपाल सिंह, हीरो साइकिल (मंगली डिवीजन) पर संयुक्त सचिव जगदीश चन्द और एवन बाइसिकल कम्पोनेंट वर्क्स के गेट पर कामरेड सुखविंदर सिंह सेखों ने ध्वजारोहण किया।

जालन्धर, अमृतसर, संगरूर, होशियारपुर, नवांशहर, पठानकोट, रोपड़, डेरा बस्सी, नंगल, गढ़शंकर, अहमदगढ़, राजपुरा, मलेर कोटला, चमकौर साहेब, फिरोजपुर, बुढलाडा, मलोट, अमलोह, भीखीविंड, आसरों, मुकेरियां, गुरदासपुर, जगराओं, भटिंडा, तरनतारन, मुक्तसर, मानसा, पातड़ां, बलाचौर, रायकोट, बटाला, बरनाला, धूरी, मोगा और चण्डीगढ़ के औद्योगिक केन्द्रों सहित 70 से अधिक स्थानों पर मजदूरों की ओर से अपनी–अपनी फैक्टरियों के आगे लाल झण्डे फहराए गए और जबरदस्त रैलियां निकाली गई। इन रैलियों को सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड विजय मिश्र और अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया।

दिल्ली : दिल्ली के अनेक स्थानों पर सीआइटीयू की ओर से मई दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर रामलीला मैदान से टाउन हाल तक एक संयुक्त रैली निकाली गई। सभा के प्रमुख वक्ता सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव तथा सांसद कामरेड तपन सेन थे। सीआइटीयू से सम्बद्ध होटल वर्कर्स यूनियन (रजि0) की ओर से पंडारा रोड पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 200 साथियों ने भाग लिया। समारोह का उद्घाटन सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति के महासचिव कामरेड मोहन लाल ने किया।

रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट इम्पलाईज यूनियन सम्बद्ध सीआइटीयू ने मंगोलपुरी चौक पर मई दिवस समारोह का आयोजन किया और लाल झण्डा फहराया। समारोह का उद्घाटन कामरेड मोहन लाल ने किया जबकि राज्य समिति के कोषाध्यक्ष कामरेड एच सी पंत तथा कामरेड के पी राव ने भी सभा को सम्बोधित किया।

गाजियाबाद में मई दिवस कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर–4 में किया गया जिसमें 500 साथियों ने भाग लिया। सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड सुधीर कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके अतिरिक्त कामरेड ब्रह्मजीत, जिला सचिव कामरेड के एम तिवारी तथा अन्य नेताओं ने भी सभा को सम्बोधित किया।

राजस्थान (जयपुर): सीआइटीयू की ओर से यहां अनेक स्थानों पर मई दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाल कोठी सब्जी मण्डी, अनिल स्टील बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र, जीप स्टैंड चांदपोल, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र, रोडवेज डिपो, आरएसईबी पावर हाउस, मोती महल लक्ष्मी मन्दिर सिनेमा, सफाई मजदूर प्रताप नगर, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, कृषि उपज मण्डी चांदपोल, आटो रिक्शा स्टैंड संजय सर्किल और बजरी मण्डी ट्रांसपोर्ट नगर इत्यादि स्थानों पर लाल झण्डे फहराए गए तथा जन सभाओं का आयोजन किया गया। सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव कामरेड रवीन्द्र शुक्ल, उपाध्यक्ष कामरेड वकार–उल–अहद, कामरेड हरेन्द्र सिंह और कामरेड चम्पा मुखर्जी ने इन जन सभाओं को सम्बोधित किया। हटवाडा रोड पर स्थित मजदूर किसान भवन में कामरेड वासुदेव ने लाल झण्डा फहराया जबकि कामरेड रवीन्द्र शुक्ल कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे।

बिहार (पटना) : सीआइटीयू की राज्य समिति की ओर से राज्य कार्यालय में सुबह ध्वजारोहण किया गया। सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियनों बैंक, बीमा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ, बीएसएसआर के कार्यालयों में मई दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। महासंघ के अध्यक्ष कामरेड अरुण कुमार सिंह ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। इस गोष्ठी में पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भी हिस्सा लिया जबकि सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव कामरेड अरुण कुमार मिश्र मुख्य वक्ता थे। फ्रेजर रोड पर स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय परिसर में सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियन ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बीमा, बेफी, बिहार कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभा को सीआइटीयू नेता कामरेड अरुण कुमार मिश्र, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव कामरेड मंजुल कुमार दास, बीमा कर्मचारी संघ के नेता कामरेड मिथिलेश कुमार सिंह इत्यादि नेताओं ने

पृष्ठ 13 पर

18 अप्रैल की रैलियां

हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण, आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रेड 3 व सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारियों के रूप में नियमित करने, आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर 3000रू प्रतिमाह एवं सहायिकाओं का मानदेय 2000रू प्रतिमाह करने, पूर्व नियमितिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों जिसमें पेंशन शामिल है, मांगों पर पूरे देश से विभिन्न राज्य राजधानियों में मार्च किया। इन रैलियों को करने का निर्णय अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका यूनियन की जनवरी 2006 में कोलकाता में हुई बैठक में लिया गया था। यहां कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत हैं–

आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने झुलसती गर्मी में इन्दिरा पार्क से सुंदरैया विज्ञान केंद्रम, हैदराबाद तक अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन तथा अखिल भारतीय मांगों के साथ अपनी पूर्व की मांगों पर नारे लगाते हुए मार्च किया। राज्य सभा की सांसद पीमधु ने विश्वास दिलाया कि वे संसद में उनके मुद्दे उठाऐंगी। आंध्र प्रदेश की आंगनवाड़ी यूनियन की महासचिव पी रोजा, सीटू राज्य कमेटी की उपाध्यक्ष एस पुन्यावती, एमएलए गफ्फूर, एडवा की वेटरन नेता एम स्वराज्यम तथा अन्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यूनियन की अध्यक्ष बी ललितम्मा ने बैठक को संबोधित किया। एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला और मांगपत्र जमा करवाया। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार मानदेय में वृद्धि कर भुगतान करेगी।

बारह जिलों से लगभग 7000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन, पंजाब के झंडे तले एक विशाल जुलूस तथा प्रदर्शन चण्डीगढ़ में मटका चौक पर हुआ। रैली को यूनियन की अध्यक्ष हरगोविंद कौर, महासचिव करमजीत कौर, वित्त सचिव ऊषा, सीटू पंजाब राज्य कमेटी के महासचिव रघुनाथ सिंह, यूनियन के कुछ अन्य नेताओं व दूसरे संबंधित संगठनों ने संबोधित किया।

पूरे राज्य से 5000 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बैंगलूर, कर्नाटक में विशाल जुलूस तथा रैली में भाग लिया। एस वारालक्ष्मी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गवर्नर तथा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से मिले तथा मांगों पर बातचीत की। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने विश्वास दिलाया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए पेंशन के प्रस्ताव तथा अन्य मांगों पर गंभीरता से विचारा जाएगा। यूनियन के नेताओं, सीटू एवं दूसरे संबंधित संगठनों ने रैली को संबोधित किया।

असम में भारी वर्षा, बीहू त्योहार तथा राज्य सभा चुनावों की समाप्ति द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को झेलते हुए जिला स्तर पर 9 जिलों में रैलियां हुईं। इन रैलियों में 3000 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

पटना, बिहार में एक आकर्षक जुलूस तथा रैली हुई जिसमें 7 जिलों से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। आइफा की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने रैली को संबोधित किया। आयोजक कमेटी की संयोजिका आशा देवी एवं सीटू के बिहार राज्य कमेटी सचिव अरूण मिश्रा ने भी रैली को संबोधित किया।

मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों से सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 18 अप्रैल को भोपाल में रैली तथा जुलूस में भाग लिया। सीटू की मध्य प्रदेश राजय कमेटी के महासचिव बादल सरोज, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एकता यूनियन की अध्यक्षा विद्या खंगार तथा एडवा की राज्य अध्यक्षा संध्या शैली ने रैली को संबोधित किया।

सीटू तथा आइफा से संबद्धित उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के झंडे तले पहली बार सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने धरने में भाग लिया। आइफा की महासचिव हेमलता भी वहां मौजूद थीं। आइफा की कार्यकारिणी कमेटी की सदस्या अनसूया सिंह, यूपी राज्य कमेटी के महासचिव दौलत राम, एडवा राज्य कमेटी की सचिव मधु गर्ग तथा अन्य सीटू नेताओं ने भीड़ को संबोधित किया। वीना गुप्ता ने अध्यक्षता की। बाद में सीटू दफ्तर में राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 8 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक राज्य स्तरीय आयोजक कमेटी गठित की गई, जिसमें वीना गुप्ता को संयोजिका बनाया गया। विभिन्न जिलों में सदस्य बनाने, परियोजना, जिला एवं राज्य अधिवेशन कर संगठन बनाने के प्रयास आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लगभग 2000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया। सीटू की जम्मू एवं कश्मीर राज्य कमेटी के अध्यक्ष तारीगामी तथा यूनियन के अन्य नेताओं ने रैली को संबोधित किया। जम्मू के डोडी व उधमपुर जिलों में भी रैलियां हुईं।

18 अप्रैल को महाराष्ट्र के पूना, चन्द्रपुर तथा जलना में जुलूस तथा रैलियां हुईं जिसमें सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

छत्तीसगढ़ में 18 अप्रैल 2006 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से रायपुर के मोतीबाग में दिनभर धरना दिया गया। धरने में कोरबा, राजनंदगांव, दुर्ग एवं रायपुर जिले की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत लगभग 900 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। ये महिलाऐं शहरी परियोजनाओं के साथ–साथ सुदूर आदिवासी अंचल चौकी, छुरिया आदि परियोजनाओं से भी आई थीं। यूनियन की महासचिव उमा नेताम ने धरनाकारी महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें निरन्तर संघर्ष के लिए तैयार रहने का आहवान किया। धरने में दिन भर चली सभा को गजेन्द्र झा, स्नेह लता सोहनी, चंदा बारबोटे, बिलकिस बेगम, अरूणा वैष्णव, माया ओझा तथा जे पी टिकारिहा के अतिरिक्त सीआईटीयू की छत्तीसगढ़ राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड ए के लाल ने भी सम्बोधित किया। सभा की कार्यवाही का संचालन यूनियन की कोषाध्यक्ष रम्भा पवार ने किया।

केरल, पांडीचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटियों ने चुनावों के कारण रैलियों को बाद में करने का निर्णय लिया। □

यूपीए सरकार के दो वर्षो के कार्यकाल का लेखाजोखा

□ हेम लता

केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने शासन काल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2004 के लोक सभा चुनावों में देश की जनता ने निर्णायक तौर पर विकास के नव–उदार आर्थिक नीतियों के माडल को रद्द कर दिया था। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इसी माडल को सामने रख कर काम कर रही थी; इसके साथ ही उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी की ओर से अपनी साम्प्रदायिक कार्यसूची को भी आगे बढ़ाया जा रहा था। यूपीए को सत्ता में लाकर देश की जनता ने उन नीतियों को लागू करने के लिए जनादेश दिया था जो जन साधारण, मजदूरों, किसानों तथा बेरोजगार लोगों के लाभ में हों। वाम पक्षी दलों ने संसद में अपनी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी दर्ज कराई। वास्तव में, वाम पक्षी दलों के दबाव में यूपीए को राष्ट्रीय संयुक्त न्यूनतम कार्यक्रम को अपनाना पड़ा है और उस कार्यक्रम में वह कुछ जन पक्षीय आश्वासनों एवं प्रतिबद्धताओं को जोड़ने के लिए भी मजबूर हुई है। यूपीए सरकार की पिछले दो वर्षो की कारगुजारी की समीक्षा करते समय इस पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद देश की राजनीति में एक प्रमुख सकारात्मक बदलाव आया है; राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिक मुद्दों को उभारे जाने के स्थान पर बेरोजगारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, विनिवेश इत्यादि जन हित के मुद्दे चर्चा का विषय बन चुके हैं। सरकार ने पोटा को निरस्त करने तथा सूचना के अधिकार सम्बन्धी अधिनियम बनाने जैसे कुछ काम जनता के जनवादी अधिकारों को सुनिश्चित बनाने के लिए किए हैं। उसने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा तथा सम्पत्ति में उनके अधिकार को लेकर कानून बनाए हैं। वाम पक्षी दलों, श्रमिक संघों तथा जनता की दूसरी श्रेणियों द्वारा संसद के भीतर तथा संसद के बाहर जबरदस्त दबाव डाले जाने के कारण सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाने के लिए मजबूर हुई है। वर्तमान में भले ही यह कानून देश के केवल 200 जिलों तक सीमित है और शहरी क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को भी इस कानून के दायरे में लाया जाना अभी बाकी है।

प्रतिबद्धताएं जिन्हें भुला दिया गया

किन्तु एनसीएमपी मे व्यक्त की गई अनेक प्रतिबद्धताओं के मामले में सरकार की ओर से गम्भीरता पूर्वक प्रयास नहीं किए गए। महिला संगठनों की ओर से बार–बार मांग किए जाने पर भी महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश नहीं किया गया; असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित विधेयक पर सरकार की पहलकदमी केवल विभिन्न प्रकार के परिपत्रों को जारी किए जाने तक सीमित रही है और केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए सुझावों को उसमें समाहित करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया। खेतिहर श्रमिकों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने का आश्वासन दिया गया था, उसे भी लगभग भुला दिया गया है। एनसीएमपी में आइसीडीएस के सार्वभौमिकीकरण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी किन्तु 2005 में शुरू होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में उसे लागू करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यूपीए सरकार का पिछले दो वर्षो का अनुभव दर्शाता है कि यह सरकार भी अपनी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की भांति उन्हीं विनाशकारी आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहती है जिनके कारण एनडीए को सत्ता से बाहर हो जाना पड़ा था। विदेशी नीति के मामले में यूपीए सरकार उसी तत्परता का प्रदर्शन कर रही है जो उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने साम्राज्यवादी अमरीका की कनिष्ठ सहयोगी बनने के लिए दिखाई थी।

सरकार तथा वित्त मंत्री पिछले वर्ष 8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के मूड में दिखाई देते हैं। तथ्य तो यह है कि आज भी हमारे देश की 70 प्रतिशत जन संख्या .षि पर निर्भर करती है और .षि इन दिनों गहरे संकट की दलदल में धंसी हुई है। ब्रिटिश शासन के जमाने के शासकों की तरह इस सरकार को भी इसकी कोई चिंता नहीं है। देश में अनाज के उत्पादन में गिरावट आ गई है और अपनी बदतर हालत से परेशान होकर किसानों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने के समाचार हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहे हैं। .षि के लिए धन का आबंटन जरूरत से कहीं कम किया जा रहा है। इन्हीं दोषपूर्ण .षि नीतियों के कारण सरकार आज अनाज का आयात करने पर मजबूर हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी तथा श्रमिकों का उत्प्रवास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यह अब चौंका देने वाली सीमा तक पहुंच चुका है।

भारत में कुपोषण का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है। एक सामान्य धारणा के विपरीत भारत में कुपोषण का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या सब–सहारा देशों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों से दोगुणा है। हमारे लगभग आधे से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। इसका दुष्प्रभाव न केवल उनके शरीर पर पड़ता है बल्कि उनका मानसिक विकास भी ढंग से नहीं हो पाता; इसके चलते भावी पीढ़ियों में मेधा का विकास तथा उत्पादकता की क्षमताएं भी प्रभावित हुई हैं। किन्तु सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं और वह लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने

के लिए कतई गम्भीर नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग धाराशायी हो चुकी है; नव–उदार नीतियों के चलते गरीब लोगों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडियां खत्म प्रायः की जा चुकी हैं।

दोषपूर्ण कार्रवाईयां

जहां राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ पर चलने वाले उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जाएगा वहीं इसके विपरीत सरकार वामपक्षी दलों तथा श्रमिक संगठनों के विरोध के बावजूद निजीकरण तथा विनिवेश की कार्रवाईयां करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसने अपने एससीएमपी में वादा किया था कि वह श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मुद्दों पर श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श करेगी किन्तु सरकार ने श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी मुद्दे पर श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श करने का प्रयास नहीं किया है और न ही उसने श्रमिक संघों द्वारा दिए गए सुझावों को गम्भीरता से लिया है। वह वामपक्षी दलों की ओर से दिए गए ठोस सुझावों की भी अनदेखी कर रहा है। दिल्ली तथा मुम्बई के हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। अब भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण के श्रमिकों के साथ हुए समझौते के विपरीत सरकार दूसरे हवाई अड्डों में भी इस योजना के अनुसार काम करना चाहती है। एएआइ लाभ पर चलने वाला उपक्रम है और वह खुद आधुनिकीकरण करने में समर्थ है फिर भी सरकार हवाई अड्डों के निजीकरण की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है।

सरकार पेन्शन निधियों का भी निजीकरण कर देना चाहती है और पेन्शन नियामक प्राधिकरण विधेयक के माध्यम से वह इन निधियों में जमा पैसा शेयर बाजार में लगाने को आतुर है। शेयर बाजार की घटनाएं सीआइटीयू तथा दूसरे श्रमिक संगठनों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं को सही सिद्ध करती हैं। उन्होंने कहा था कि यदि श्रमिकों की पेन्शन का धन शेयर बाजार में लगाता है तो वे संकट में पड़ जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों की दुहाई देकर पिछले दो वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में चार बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। सरकार एक बार फिर इनके मूल्यों में बढ़ोतरी करने जा रही है। अनिवार्य उपभोग की दूसरी वस्तुओं के मूल्यों पर इसका प्रपाती प्रभाव पड़ेगा। उनके मूल्य पहले ही बढ़ रहे हैं। वामपक्षी दलों ने पेट्रोलियम पदार्थों के लिए कराधान के ढांचे की समीक्षा करने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। सरकार ने उन सुझावों को मानने से इन्कार कर दिया है।

वामपक्षी दलों और श्रमिक संघों के विरोध करने पर भी सरकार बीमा, दूरसंचार जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू कर रही है। उसने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण करने की अनुमति विदेशी बैंकों को दे दी है और इसके लिए वह बैंकिंग नियामक अधिनियम में बदलाव लाना चाहती है। उसने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है जिसका देश में लाखों छोटे व्यापारियों के रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा।

शेयर बाजार के हाल ही के संकट और बाजार की संकटग्रस्तता के चलते फुल केपिटल एकाउंट कनवर्टिबिलटी का खतरा पैदा हो गया है। प्रधान मंत्री ने पहले ही इसके बारे में घोषणा कर दी थी। सरकार ने लम्बी मुद्दत के पूंजी लाभों पर कर लगाने और इसी तरह की दूसरी कार्रवाईयां करने से इन्कार कर दिया है। सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए सरकार अतिरिक्त धन जुटा सकती थी पर उसने लम्बी मुद्दत के पूंजी लाभों पर कर लगाने और इसी तरह की दूसरी कार्रवाईयां करने से इन्कार कर दिया है।

यूपीए के राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में वादा किया गया था कि सरकार जनता के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगी। किन्तु व्यवहार में यूपीए सरकार इससे द्रोह कर रही है और वह एशिया में अमरीका की कनिष्ठ सहयोगी बनने के लिए आतुर है। अमरीका के दबाव में सरकार को ईरान के नाभिकीय मुद्दे पर अपने रुख में बदलाव लाना पड़ा है और उसने इस प्रश्न पर ईरान के खिलाफ वोट दिया है। इसका दुष्प्रभाव ईरान गैस पाइप लाईन की परियोजना पर पड़ेगा, यह स्वाभाविक है। केवल विदेश नीति की बात नहीं है घरेलू नीतियों के मामले में भी यह सरकार अधिकाधिक अमरीका के दबाव में आकर काम कर रही है। इन नीतियों को लागू करने के मामले में योजना आयोग एक प्रमुख केन्द्र बन चुका है। यह बात राष्ट्रीय सांझे न्यूनतम कार्यक्रम की मूल भावना के विपरीत है।

विश्व बैंक के इशारों पर लागू की जा रही नव–उदार भूमण्डलीयकरण की नीतियों का विरोध विश्व भर में बढ़ रहा है; लोगों का उससे मोह भंग हो रहा है; लातिनी अमरीका की घटनाओं, फ्रांस तथा दूसरे देशों में चल रहे संघर्षों से यह संकेत मिलता है। हाल ही में सम्पन्न पांच राज्यों की विधान सभा चुनावों के परिणामों और पश्चिम बंगाल 1ध4लगातार सातवीं बार1ध2 तथा केरल में वाम पक्षी दलों की विजय से यही संकेत मिलता है कि जनता वैकल्पिक नीतियां चाहती है।

अब समय आ गया है कि श्रमिक वर्ग वैकल्पिक नीतियों के लिए जारी संघर्षों को तीखा करे और उनका नेतृत्व करे; देशव्यापी जुझारू संघर्षों को विकसित करे। ये संघर्ष केवल श्रमिकों की सीधी समस्याओं को लेकर ही नहीं अपितु समग्र रूप में जन समस्याओं को लेकर चलाने होंगे। संघर्षों को और तीखा करके ही यूपीए सरकार पर जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। □

वाम की जीत

पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावों में लगातार सातवीं बार वाम मोर्चा विजयी रहा; उसे विधान सभा में तीन चौथाई बहुमत हासिल हुआ; बहुदलीय व्यवस्था में यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है। सीपीआई(एम) के नेतृत्व में वामपंथ ने 293 सीटों में से 235 सीटें जीतीं (कुल 294 सीटों में से एक के लिए चुनाव एक प्रत्याशी की मृत्यु के कारणवश स्थगित किया गया था)। सीपीआई (एम) ने स्वयं अपने दम पर 176 सीटें जीतीं।

वामपंथी दलों पर आमतौर पर ऐसे अनर्गल लगते रहते है कि वह चुनावों में वैज्ञानिक धांधली करते है और मतदाता सूचियों में गड़बड़ करते है इत्यादी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पांच चरणों में चुनाव कराने की घोषणा कर ऐसे प्रयासों में और मदद पहुंचाई जबकि तमिलनाडु में चुनाव केवल एक बार कराए गए, 6000 अर्धसैनिक बल तैयार किए गए, चुनाव कमिश्नर ने स्थानीय पुलिस पर भरोसा नही किया, प्रेक्षक बाहर से लाए गए, चुनाव कमिश्नर ने बंगाल अफसरो पर विश्वास नही किया, बैनरों, झंडा फहराने, दीवार लेखन इत्यादी समेत तमाम तरह के चुनाव अभियानों पर पाबंदी लगाई गई, लाखों ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए जिनके पास फोटो पहचान पत्र था। ऐसा 'पूरी तरह सही मतदाता सूचियां तैयार करने' के नाम पर किया गया। सीपीआई(एम) के दफ्तरों पर छापा मारा गया। हमेशा की तरह लोग घरों से बाहर आए और उन्होनें मत दिए।

इन लगातार जीतों का रहस्य क्या है? लगातार सातवीं बार वामपंथ कैसे जीत सकता है? अंतर यह है कि जब राष्ट्रीय अनुभव या अन्य राज्यों के अनुभव है कि यह ग्रामीण जनता की शक्ति के आधार पर सत्ता में आई हैं। इसी संबंध में स्टालिन की बात को भूला नही जा सकता कि हम इसे एक नियम के रूप में ग्रहण करते हैं कामरेड स्टालिन ने कहा कि जैसे जैसे बोल्शेविक अधिक से अधिक जनता से संबंध बनाऐंगें, वे अजेय रह पाऐंगें।

प्राचीन ग्रीकों की कथाओं में एक एन्टेइयस नामक हीरो था जोकि समुद्रों के देवता तथा भूमि की देवी का पुत्र था, उसका अपनी माँ के प्रति बहुत लगाव था। वहां कोई ऐसा कोई नायक नही था जो उसे जीत सके। परन्तु उसे शक्ति कहाँ से मिलती थी? उसे लड़ने के लिए शक्ति उसे जन्म देने वाली माँ, भूमि (जमीन) के स्पर्श से मिलती थी। जब वह जमीन छूता, उसे एक नई मजबूती प्राप्त होती। उसके शत्रु उसकी कमजोरी से अवगत थे और उस पर नज़र रख रहे थे। एक दिन उसके शत्रुओं ने उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर एन्टेइयस को जीत लिया। वह हरक्यूलिस था। हरक्यूलिस ने एन्टेइयस को कैसे जीता? उसने एन्टेइयस को जमीन से ऊपर उठाया, उसे जमीन का स्पर्श नही करने दिया और उस पर घात कर पराजित कर दिया।

मेरे विचार से बोल्शेविक हमें ग्रीक कथा के एन्टेइयस की याद दिलाते है। वे एन्टेइयस की तरह मजबूत हैं क्योंकि वे जन्म देने वाली माँ अर्थात् आवाम के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। जब तक वे अपनी मां अर्थात् जनता के साथ संपर्क बनाए रखेंगें, वे अडिग रह पाऐंगें। जनता के साथ संबंध बनाना, उनकी समस्याओं को समझाना तथा उस पर प्रतिक्रिया करना, जनता को विश्वास दिलाना ही पश्चिम बंगाल में वाम पंथ की जीत का रहस्य है।

केरल में भी वामपंथ की जीत की संभावना थी। एलडीएफ ने दो तिहाई बहुमत से 140 सीटों में 98 सीटें जीतीं। केरल की जनता यूडीएफ की नीतियों से नाराज़ थी। पिछले पांच वर्षो के दौरान सीटू के नेतृत्व में मजदूर वर्ग ने विकास के नाम पर यूडीएफ न उदारवादी नीतियों के विरूद्ध बहुत से संघर्ष किए। असंगठित क्षेत्र मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों के बहुत से मुद्दों पर अभियानों में लाखों लोगों ने भाग लिया। वामपंथ ने भी केरल के विकास के लिए एक विकल्प प्रस्तुत किया तथा उस पर अभियान चलाए।

तमिलनाडु में जयललिता उनका भरोसा जीतने में विफल रही। राज्य सरकारी कर्मचारियों को जीतने के प्रयत्नों के बावजूद, वे 2002 की हड़ताल के दौरान उनके साथ किए जाने व्यवहार को नही भूले। तमिलनाडु विधान सभा में वामपंथ मजबूत हुआ है। तथा आसाम विधान सभा में भी वाम ने अपनी मजबूती बढ़ाई है।

परन्तु यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विधान सभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। केरल में 12वें विधान सभा चुनाव में 64 महिला प्रतिनिधियों में से केवल 7 महिलाएं चुनी गईं। वे सभी एलडीएफ से संबंधित हैं– सीपीआई(एम) से 6 तथा सीपीआई से एक। वे सभी महिलाएं आंदोलनो की नेता हैं। तथा पश्चिम बंगाल में 294 में से 29 महिलाओं ने सीटें जीतीं।

पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव 2006 का जनादेश जिसने वाम मोर्चे को 294 में से 235 सीटों पर जीत दिलाई है, राज्य का जन पक्षीय विकास के लिए है; यह जनादेश भूमण्डलीयकरण की जन विरोधी प्रक्रियाओं के खिलाफ संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ने के लिए है और केन्द्रीय सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहने का आह्वान करता है। □

भारत के अल्प पोषित बच्चे

अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के कुपोषित बच्चे–सुधार एवं कार्यवाही का आहवान नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत के कुपोषित बच्चों की समस्याओं को लेकर गम्भीरता दर्शायी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामान्य से कम वजन के बच्चों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है। एक सामान्य धारणा के विपरीत भारत में सामान्य से कम वजन के बच्चों की संख्या सब–सहारा देशों में कम वनज के बच्चों से दोगुणा है।

हमारे देश में लगभग 30 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के पैदा होते है। 1998–99 में लगभग 75 प्रतिशत भारतीय बच्चे जिनकी आयु तीन वर्ष से कम है, सामान्य से कम वजन के हैं (47 प्रतिशत बच्चे कम वजन या सेवेरली कम वजन के थे और अन्य 26 प्रतिशत दयनीय रूप से कम वजन के थे)। कम वजन का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 38 प्रतिशत है। लड़कों (45.5 प्रतिशत) की तुलना में लड़कियों (48.9 प्रतिशत) में कम वजन का प्रभाव अधिक है। तथा यह समाज के पिछड़े विभागों में अधिक है जैसे अनुसूचित जाति के परिवारों में 56.2 प्रतिशत बच्चे तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 53.2 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पैदा होते है जबकि तुलना में अन्य जातियों में इसका प्रतिशत 44.1 प्रतिशत है। और निर्धन परिवारों में लगभग 60 प्रतिशत बच्चे कम वजनीय पैदा होते हैं।

इसका दुष्प्रभाव न केवल उनके शरीर पर पड़ता है, बल्कि उनका मानसिक विकास भी ढंग से नहीं हो पाता; इसके चलते भावी पीढ़ियों में मेधा का विकास नही हो पाता तथा वे बीमारियों से पीड़ीत हो जाते है मुख्य रूप से जैसे–डायरिया, मलेरिया इत्यादी। ये सब इन्हें और अधिक कुपोषित बना देते है। यह अनुमान लगाया गया कि देश में लगभग में आधे से अधिक बच्चों की मृत्यु कुपोषण से हुई। कुपोषण के अन्तर्गत आधे से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया (61 प्रतिशत), मलेरिया (57 प्रतिशत), तथा निमोनिया (52 प्रतिशत) होती है तथा 45 प्रतिशत छोटी माता से भी से होती है।

इस स्थिति के गम्भीर होने के कारण केवल अधिक संख्या में बच्चों का कुपोषित होना ही नही है। यह हमारे देश के भविष्य से संबंधित है क्योंकि बच्चे किसी भी देश के भविष्य है। यह उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर दीर्घावधि प्रभाव डालता है एवं व्यस्क होने पर उनकी स्मृति क्षमता, कुशल विकास, उत्पादकता पर भी प्रभाव डालता है।

रिपोर्ट यह दर्शाती है कि पिछले दशक में भारत में कुपोषण घटाने में सुधार में विलंब हो रहा है। कम वजन का प्रभाव 1992/ 93 में 53 प्रतिशत था जोकि 1998/ 99 घटकर 47 प्रतिशत हुआ है। (उसी बीच चीन में कम वजन का प्रभाव जोकि किसी भी केस में भारत से कम था, 2002 में घटकर 8 प्रतिशत हो गया जोकि 1990 में 19 प्रतिशत था) । चीन में पांच मृत्यु दर 1990 में 49 प्रति एक हजार से घटकर 2004 में 31 हो गई। कम वजन के बच्चों के जन्म लेने की घटना केवल 4 प्रतिशत रह गई।

देश में बच्चों में कुपोषण तथा सामान्य से कम वजन का होना केवल उनके लिए शुरूआत है जो सेंसेक्स के बढ़ते हुए ग्राफ तथा वृद्धि दर से अनभिज्ञ है। तथा थ्योरी पर विश्वास करते है तथा सोचते है कि सामान्य जन एवं निर्धनों के लिए सब ठीक हैं परन्तु यह उनके लिए शुरूआत नही जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामान्य जनों की हर असलियत से वाकिफ हैं।

नव उदारवादी आर्थिक नीतियां जिनका पालन केंद्र से सफल सरकारों द्वारा हो रहा है देश में संकट का नेतृत्व कर रही है। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। संगठित क्षेत्र जिन्हें कुछ रोजगार सुरक्षा व काम के स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, डगमगा रहे हैं, असंगठित क्षेत्र फैल रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई रोजगार सुरक्षा नही मिलती, न्यूनतम मजदूरी नही मिलती तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नही है। देश में खाद्य तथा उपभोग स्तर गिर रहा है।

ऐसे समय में जब सरकार न्यूनतम सामाजिक कल्याण लाभों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादी, उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व से पीछे हट रही है वहीं निर्धनों को अपनी आय का बहुत बड़ा भाग स्वास्थ्य जैसे पोषक भोजन, कुपोषण द्वारा फैली बीमारियों, पीने के पानी का अभाव इत्यादी पर व्यय करना पड़ता है।

वे अच्छे रहने के लिए इलाज के आशा में, कार्य करने के योग्य रहने, धन अर्जन करने, लोन की राशि चुकाने, तथा खुश रहने के लिए धन उधार लेने के लिए बाध्य हैं। वे अपने खाद्य उपभोग में कटौती करते हैं। उनमें से बहुत से लोगों के पास बीपीएल कार्ड भी नही हैं और जिनके पास है वे नियमित रूप से राशन भी नही लेते, और जो लेते हैं उनके पास इसे खरीदने के लिए धन भी नही है।

नाम के अनुसार भारत के कुपोषित बच्चे–सुधार एवं कार्यवाही का आहवान रिपोर्ट का लेखक के इन गम्भीर समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ सुझावों को संबोधित करता हैं। वह है आईसीडीएस में सुधार । यहां कार्यक्रम की इंटेशन तथा असल पालन में कुछ मतभेद है और यदि यह विश्व बैंक द्वारा सुझावित वाक्यों में सही है तो कुपोषण तथा

पृष्ठ 8 पर

ट्रेड यूनियनों की स्पोंसरिंग कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन

एआईसीसीटीयू, एटक, सीटू, एचएमएस, यूटीयूसी, यूटीयूसी–एलएस, टीयूसीसी तथा अखिल भारतीय बैंक फैडरेशन, भविष्य निधि, रेलवे, केंद्रिय तथा राज्य सरकारी कर्मचारी, प्रतिरक्षा, सिविल ऐविटेशन तथा अन्य क्षेत्रों सहित ट्रेड यूनियनों की स्पोंसरिंग कमेटी ने मजदूर वर्ग तथा अन्य विभागों की मांगों तथा नई दिल्ली में 25 जुलाई 2006 को मजदूर वर्ग के राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंधित मुद्दों पर देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रमों की समय–सारणी तथा देशव्यापी गतिविधि का निर्णय सम्मेलन में होगा।

देशव्यापी अभियान तथा कार्यक्रम में उठाए जाने के लिए मजदूर वर्ग के कुछ मुद्दे तथा फौरी मांगें–

- आवश्यक व्यापार की वस्तुओं पर बढ़ते दामों को तुरन्त रोका जाए।
- दाम बढ़ाने की बजाय पैट्रोलियम उत्पादों के कर ढ़ांचे को पुनः बनाया जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करो।
- भारत की खाद्य सोवर्निटी को खतरे में डालना बंद करो
- उपभोक्ता कीमत सूची की नई श्रंखला वापस करो जोकि वेतन भुगतान में कटौती का कारण है।
- खेती के संकट को हल करने के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम चलाओ जिसमें आयात नीतियों की वापसी भी शामिल है।
- सभी खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए सुरक्षित कानून लाओ।
- असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा इत्यादी सुनिश्चित करने के लिए कानून पास करो।
- श्रम कानूनों में श्रम विरोधी परिवर्तन बंद करो।
- श्रम कानूनों को लागू करवाने वाली मशीनरी को मजबूत करो।
- लाभ कमाने वाली इकाइयों और रणनीतिक क्षेत्र के नीजिकरण, विनिवेश पर रोक लगाओ
- आर्थिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के प्रयत्न बंद करो।
- बिजली कानून 2003 और राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 की समीक्षा करो। □

पृष्ठ 7 का शेष

सामान्य से कम वजन की सभी समस्याएं भारत से गायब ही हो जाएंगी।

इस रिपोर्ट के अनुसार आईसीडीएस कार्यक्रम भारत में बच्चों के पोषण संबंधी समस्याओं को बहुत भली प्रकार से संबोधित करता है। परन्तु यह खाद्य वितरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जिसे बैंक ने परिवर्तित करना महसूस किया। इसलिए आईसीडीएस में सुधार ताकि यह पारिवारिक आधार पर खिलाने व अच्छे व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके जैसे माताओं स्तनपान के लाभों के बारें में बताना।

विश्व बैंक की सिफारिश कि इस कार्यक्रम को कुछ ऐसे जिलों या गावों में जहां कुपोषण तथा सामान्य से कम वजन का प्रभाव है, में लक्षित करना, उच्चतम न्यायालय के आईसीडीएस को व्यापक बनाने के आदेश तथा यूपीए सरकार के एनसीएमपी में की गई प्रतिबद्धताओं के विपरीत है।

केंद्र से सरकारे जन विरोधी आर्थिक नीतियों का सफलतापूर्वक पालन किया में किन्तु सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं और वह लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कतई गम्भीर नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग धाराशायी हो चुकी है; नव–उदार नीतियों के चलते गरीब लोगों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडियां खत्म प्रायः की जा चुकी हैं।

रिपोर्ट में कहीं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सेविकाओं की दयनीय दशा के बारे में कुछ भी नही है। दूसरी ओर इसकी सिफारिशें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सेविकाओं को इस समूह में शामिल नही करती क्योंकि सरकार इन्हें इनकी सेवाओं का भुगतान कर रही है। यह सिफारिश करती है कि कार्यक्रम के संचालन के लिए साधन समाज से एकत्र किए जाने चाहिए। यह आंध्र प्रदेश की ''मदर्स कमेटियों'' को मॉडल मानकर आंगनवाड़ी केंद्रों की देखभाल व नई भर्ती के लिए इनका पालन करने की भी सिफारिश करती है।

इसमें कोई दोराय नही है कि आईसीडीएस में सुधार की आवश्यकता है, परन्तु बच्चों का पोषण स्तर किन्ही कार्यक्रमों पर निर्भर नही करता। आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को स्थाई बनाकर, इसे संस्थागत बनाने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सेविकाओं को ग्रेड 3 व ग्रेड 4 के सरकारी कर्मचारी कर्मचारी के रूप में नियमित करने की आवश्यकता है।

सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, इसके लाभार्थियों के संगठन जैसे महिला, खेतिहर मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, ट्रेड यूनियनें इत्यादी आईसीडीएस को मजबूत बनाने के लिए उपरोक्त मांगों के साथ एकजुट होकर आएं। □

आइफा की विराट क्रमिक भूख हड़ताल की योजना

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका फैडरेशन की विस्तारित कार्यकारिणी कमेटी बैठक 5 जून 2006 को हैदराबाद में हुई, जिसमें दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद के समक्ष विराट भूख हड़ताल के लिए विस्तारित योजना बनाई गई। क्रमिक भूख हड़ताल की मुख्य मांगे होंगी– नियमितिकरण, मानदेय में वृद्धि, पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ इत्यादी। क्रमिक भूख हड़ताल में दस दिन में प्रत्येक दिन विभिन्न राज्यों से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं भाग लेंगीं।

आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियनों के लगभग 115 नेतागण– आइफा के कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य तथा 19 राज्यों जैसे– आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडीचेरी, पंजाब, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में इससे संबंधित यूनियनों के पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने की। कार्यकारिणी कमेटी ने पिछली बैठक के बाद आंदोलनों में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजली दी। फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने पिछली बैठक के बाद की गतिविधियों की रिपोर्ट तथा भविष्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने लेखजोखा प्रस्तुत किया जोकि एकमत से स्वीकारा गया।

बैठक में पर्चे बांटकर, क्षेत्रिय एवं परियोजना स्तर पर जनरल बॉडी बैठकों, पोस्टरों द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर एक विशाल अभियान चलाने का निर्णय लिया। अभियान के दौरान संभवतः अधिक सक अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों तक पंहुचने के लिए राज्य कमेटियों का आहवान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य कमेटियां कार्यक्रम के लिए जमायत एवं संगठित करने के लिए विस्तृत रूप में योजनाएं तैयार करेंगी।

अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के कुपोषित बच्चे–सुधार एवं कार्यवाही का आहवान नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की।इस रिपोर्ट ने आईसीडीएस की सही दृष्टि की प्रशंसा की परन्तु ऐसी सिफारिशें भी कीं जिनको लागू करने से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को व इसके लाभार्थियों को नुक्सान पहुंचता है। कार्यकारिणी कमेटी में इन सुझावों पर भी विचार किया गया तथा इसके नकारात्मक प्रभावों को दर्शाने के लिए एक विशाल अभियान चलाने तथा सरकार पर इन सिफारिशों को न मानने के लिए दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा इसके लाभार्थियों के बीच अभियान के लिए नोट तैयार किया गया।

कार्यकारिणी कमेटी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रेड 3 व ग्रेड 4 के कर्मचारी के रूप में पंजीकृत करने तथा इनकी सेवाओं को नियमित करने तथा आईसीडीएस कें सर्वव्यापीकरण के बारें में यूपीए सरकार के रवैये पर अपनी नाराज़गी जताई। दाम बढ़ाने के संबंध में भी सरकार के पांचवीं बार पैट्रोल तथा डीज़ल के दाम बढ़ाने के प्रयत्नों पर भी नाराज़गी जताई। कार्यकारिणी कमेटी ने फैडरेशन द्वारा जमा किए पैटिशन के निरीक्षण के बाद राज्य सभा की पैटिशन कमेटी की सकारात्मक सिफारिशों का तुरन्त पालन करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का भी निर्णय लिया।

कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 3 से 4 जून को संगठन पर राष्ट्रीय कार्यशाला से पहले हुई। सीटू सचिव कनाई बैनर्जी ने कार्यशाला तथा कार्यकारिणी कमेटी की बैठक दोनों में भाग लिया।

संगठन पर कार्यशाला में हेमलता द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट के आधार पर गहराई से विचार किया गया। संगठन के चार विभिन्न भागों पर राज्यानुसार सामूहिक विचार हुए। संतोषजनक रूप से यह नोट किया गया कि हमारी सदस्यता जोकि 1989 में इसके बनने के समय लगभग 40,000 थी, अब बढ़कर 2,50,00 से अधिक हो गई है। फैडरेशन लगभग देश के सभी राज्यों में पहुंच गई है। जैया के कार्यशाला में महसूस किया गया कि फैडरेशन का मान सम्मान तथा इससें संबद्धित यूनियनों सदस्यता से प्रभावित नही हुईं। बहुत से समूहों ने सदस्यता को बढ़ाने व सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हिन्दी भाषी राज्यों में संगठन को मजबूत बनाने के निर्णयों का पुर्नविन्यास किया गया। इस वर्ष के अंत तक सभी राज्यों में ऐसी ही कार्यशालाएं करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन तथा सीटू राज्य कमेटी का कार्यशाला तथा विस्तारित कार्यकारिणी कमेटी की बैठकों के लिए हैदराबाद में अच्छी व्यवस्था करने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया गया। □

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर धोखेभरी सरकारी विज्ञापनबाजी

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को सही ठहराने के लिए सरकार की ओर से छेड़ी गयी विज्ञापन मुहिम पर सीटू ने 8 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया था:

पैट्रोल तथा डीजल की कीमतों में अपनी सरासर अनुचित बढ़ोतरी को उचित ठहराने के लिए सरकार ने जो विज्ञापन अभियान छेड़ा है, उसकी सीटू भर्त्सना करती है। इस विज्ञापनबाजी में तेल उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था के असली मुद्दे को लिया ही नहीं गया है, जबकि यह व्यवस्था पूरी तरह से अपारदर्शी बनी हुई है। सरकार को जनता को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि लोगों को करों व शुल्कों के रूप में एक लीटर पैट्रोल पर 25 रु० तथा एक लीटर डीजल पर 12 रु० अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं जबकि कच्चे तेल की लागत 18 से 19 रु० लीटर से ज्यादा नहीं बैठेगी? और क्या वजह है कि तेल विपणन की नवरत्न कंपनियों को करों की मद में राहत देने के बजाय, सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता अपनाया है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि मूल्य निर्धारण की मौजूदा व्यवस्था का आधार क्या है? यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें कीमत तय करने का आधार यह नहीं होता है कि तेल के शोधन तथा विपणन की लागतों को हिसाब में लिया जाए तथा इसके साथ सभी तेल कंपनियों के मामले में, जिनमें सिर्फ तेल शोधन का काम करने वाली रिफाइनरियां भी शामिल हैं, "उचित मुनाफे" का हिस्सा भी जोड़ दिया जाए। इसके बजाय, मुनाफे और घाटे के कल्पित आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। इस विज्ञापन अभियान में यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या वजह है कि पैट्रोलियम उत्पादों के निर्यातकों को 3,500 करोड़ रु० की निर्यात शुल्क की रियायत (ड्यूटी ड्राबैक) दी जा रही है, जबकि विश्व बाजार में तेल की कीमतें पहले ही उफान पर हैं।

सीटू मांग करती है कि ओ एन जी सी तथा ऑइल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर 2,500 रु० प्रति टन की दर से इस साल एकत्र की गयी 7,500 करोड़ रु० की राशि, सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न तेल कंपनियों के हित में तुरंत नवरत्न तेल विपणन कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए काम में लाई जाए और इसका उपयोग वित्त मंत्रालय को अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए नहीं करने दिया जाए।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां आयात समतुल्यता मूल्य पर निजी क्षेत्र के तेल शोध कारखानों से भी बड़ी मात्रा में पैट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस खरीदने के लिए बाध्य हैं। सीटू मांग करती है कि तेल क्षेत्र की सार्वजनिक नवरत्न कंपनियों की दशा पर आंसू बहाने के बजाय सरकार को यह बताना चाहिए कि निजी तेल शोधकों को अतिरिक्त लाभ दिलाए जाने का क्या तर्क है। जहां सिर्फ दो साल पहले ये निजी तेल शोध कंपनियां तेल शोधन पर 7 डालर प्रति बैरल का लाभ पा रही थीं, अब उन्हें 12 डालर प्रति बैरल की कमाई मिल रही है। पुन: जहां तेल शोधन उद्योग की शोधन की औसत लागत 2 से 3 डालर प्रति बैरल ही बैठती है, अगर सबसे बड़े स्टैंड अलोन तेल शोधनकर्ता को इतना भारी लाभ कमाने दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी सरकार को काफी जवाब देने होंगे। इसलिए, सीटू मांग करती है कि सरकार पारदर्शी तरीके से एक लागत विवरणी बनाए, जिसमें कच्चे तेल की भारत में पहुंचने तक की लागत, तेल शोधन/ उत्पादन की लागत, करों व शुल्कों का हिस्सा आदि का पूरा ब्यौरा अलग-अलग दिया जाए। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस हद तक स्टैंड अलोन रिफाइनरियों को तेल शोधन से अपनी कमाई को बढ़ाने की इजाजत देने जा रही है। लेकिन, असली मुद्दों को लेने के बजाय, सरकार ने जनता को भ्रमित करने के लिए प्रचार अभियान का सहारा लिया है। सरकार को ऐसे झूठे प्रचार पर जनता का पैसा इस तरह नहीं फूंकना चाहिए।

विमल रणदिवे स्मृति व्याख्यान

भोपाल : भोपाल में कामकाजी महिला समन्वय समिति व एडवा द्वारा 10 अप्रैल 2006 को विमल रणदिवे के जन्म दिवस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें सीटू सचिव दीपांकर मुखर्जी ने कहा कि भूमंडलीकरण की आंधी का महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें कम मजदूरी पर अधिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, तथा उन्हे कार्यस्थल पर लिंग उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नही हो पाती। यद्यपि जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं फिर भी उन्हे बराबरी का दर्जा नही दिया जाता। महिलाओं को अपने अधिकारो के लिए एक होकर संघर्ष करना होगा, पुरूष भी इन संघर्षों में भाग लेंगें।सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद प्रधान ने कहा कि महिलाओं को काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। सेमिनार में भोपाल की एडवा जिला सचिव देवयानी घोष तथा सीटू के जिला सचिव एस के घोष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन पी एन वर्मा ने किया।

ग्वालियर : सीटू जिला कमेटी तथा आंगनवाड़ी यूनियन ने 10 अप्रैल 2006 को विमल रणदिवे की याद में एक सेमिनार आयोजित किया। विमल रणदिवे सीटू सचिव तथा अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका फैडरेशन की प्रथम अध्यक्ष महासचिव थीं। सेमिनार में सीटू की जनरल काउंसिल सदस्या रंजना निरूला ने कहा कि भूमंडलीकरण की आंधी में सभी मजदूरों की बढ़ती हुई बर्बादी का प्रभाव बहुत सी कामकाजी महिलाओं पर पड़ रहा है। वे कम मजदूरी पर अधिक कार्य का बोझ, भेदभाव, कार्य असुरक्षा, दबाव तथा लिंग उत्पीड़न का सामना न केवल कार्यस्थल पर करतीं हैं, बल्कि मीडीया में महिलाओं के कमोडिफिकेशन के चलते समाज तथा घर में भी बढ़ती हिंसा का सामना करतीं हैं। बदलाव के लिए संघर्ष करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि कामकाजी महिलाओं को यूनियनों में संगठित करें तथा जन आंदोलन में शामिल हों। एडवा की राज्य कमेटी अध्यक्ष संध्या शैली तथा सीटू की कार्यकारी अध्यक्ष बी पी सोनिया 60 से अधिक जन की भीड़ जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बीड़ी मजदूर, सीटू कार्यकर्ता तथा अन्य कामकाजी महिलाए व पुरूष भी शामिल थे, को संबोधित किया। कार्यवाही का संचालन कमलेश शर्मा तथा अध्यक्षता अनीता वाजपेयी ने की। एडवा की ग्वालियर जिला सचिव ब्रिजेश क्रांति शर्मा ने धन्यवाद अदा किया।

रिपोर्ट – अखिलेश यादव

गुजरात में आंगनवाड़ी बैठकें

आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की एक बैठक गुजरात में भावनगर में 13 मई 2006 को हुई। जिले की घरेलु परियोजनाओं से लगभग 45 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता एक आंगनवाड़ी सेविका चन्द्रिका बेन ने की। आइफा की महासचिव के हेमलता तथा उपाध्यक्ष शुभा शमीम ने

पृष्ठ 12 पर

पानीपत : संघर्ष के बाद स्पिनिंग मिल के मजदूर जीते

सीटू की हरियाणा राज्य इकाई और इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन ने पानीपत के स्पिनिंग (कताई) मिल मजदूरों के आंदोलन में मिली जबर्दस्त सफलता को मजदूरों की जीत बताया है और स्पिनिंग मिल के हजारों मजदूरों को क्रांतिकारी बधाई दी है।

गौरतलब है कि मई महीने की 28 तारीख से जारी आंदोलन और लगातार दस दिन चली हड़ताल के दबाव में पानीपत के जिला उपायुक्त और श्रम अधिकारी के हस्तक्षेप से 7 जून की रात फैक्टरी मालिकों ने दस सूत्री मांगपत्र संबंधी समझौते पर दस्तखत कर दिए। समझौते के तहत मिल मालिकों ने हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देने और वेतन स्लिप जारी करने की मांग मान ली है। इसके अलावा सभी फैक्टरियों में आठ दिन के भीतर हाजिरी कार्ड जारी करने, श्रमिकों की ड्यूटी की अवधि आठ घंटे तय करने और उन्हें ओवर टाइम के लिए बाध्य नहीं करने, मजदूर का इच्छानुसार ओवर टाइम करने और ओवर टाइम करनेवाले मजदूर को वेतन का दोगुना भुगतान करने, प्रत्येक श्रमिक को सप्ताह में एक दिन का अवकाश देने और हरियाणा सरकार द्वारा घोषिक अवकाश भी प्रदान करने और इस अवकाश की अवधि का वेतन नहीं काटने, महिला मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन (न्यूनतम वेतन) देने और द्वेषवश किसी भी मजदूर को काम से नहीं हटाने की मांगें भी मालिकान ने मान ली हैं। उपायुक्त महोदय ने यह आश्वासन भी दिया है कि आंदोलन के दौरान जिन मजदूरों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें जल्द वापस ले लिया जाएगा।

इस समझौता वार्ता में यूनियन की ओर से सीटू जिला सचिव आनंद जवाहरा, कोषाध्यक्ष सुनील दत्त, जयभगवान, एसए ख़ां और अन्य मजदूर प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अगले दिन 8 जून की सुबह हाली पार्क में मजदूरों ने विजय सभा की, जिसमें हजारों मजदूरों ने हिस्सा लिया। सभा को सीटू राज्य उपाध्यक्ष बलबीर दहिया, सुरेंद्र मलिक, सीटू जिला सचिव आनंद जवाहरा, कोषाध्यक्ष सुनील दत्त, एफएफआइ राज्य महासचिव जयभगवान, युवा नेता सुरेंद्र, नरेश डाहर, प्रवीन आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने मजदूरों को एकजुट होकर और अनुशासति ढंग से आंदोलन चलाकर शानदार जीत हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने रेखांकित किया कि चूंकि मालिकान ने लिखित में समझौता किया है, इसलिए वे इसे लागू करने के लिए बाध्य होंगे। वक्ताओं ने प्रत्येक फैक्टरी में सीटू की इकाइयां गठित करने का आह्वान किया, ताकि समझौते को पूर्ण रूप से लागू करवाया जा सके। सीटू ने पिटलूम और पावरलूम मजदूरों को यूनियन कार्यालय में आमंत्रित किया, ताकि इन उद्योगों में भी श्रम कानून लागू करवाने के लिए संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जा सके।

इससे पहले, 1 जून को अनाज मंडी में संपन्न विशाल रैली के साथ स्पिनिंग मिल मजदूरों के आंदोलन ने गति पकड़ी थी। सीटू राज्य कमेटी ने यह रैली आयोजित की थी, जिसमें राज्यभर के मजदूरों की ज्वलंत मांगों को उठाया गया। रैली की तैयारी के लिए सीटू राज्य और जिला कमेटी ने 20,000 पोस्टर छपवाए और सैकड़ों मजदूर बस्तियों और गांवों में सभाएं आयोजित कीं। शहीद ब्रिगेड नाट्य मंच ने मजदूरों की जिंदगी से जुड़े नाटक प्रस्तुत कर मजदूरों में जागृति पैदा की। इसी क्रम में स्पिनिंग मिल मजदूरों ने दमन-शोषण के खिलाफ हड़ताल कर दी। करीब 300 मिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई।

इसके साथ ही पानीपत औद्योगिक क्षेत्र के चारों कोनों के मजदूर सड़कों पर उतर आए। संघर्षरत मजदूरों के तेवर देखकर पुलिस-प्रशासन और मालिकान के हाथ-पांव फूल गए। पानीपत पुलिस ने स्थिति काबू न होते देख पड़ोसी जिलों से और ज्यादा पुलिस बल बुला लिया और अलग-अलग क्षेत्रों में मजदूरों के जत्थों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में सैकड़ों मजदूर घायल हो गए। महिला मजदूरों को भी नहीं बख्शा गया और पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन पर भी बेरहमी से लाठियां बरसाईं, उन्हें अपशब्द कहे और सड़कों पर घसीटा। सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया और दस मजदूरों को संगीन धाराओं के तहत करनाल जेल में बंद कर दिया गया। इससे मजदूरों में जबर्दस्त आक्रोश फैल गया। बहरहाल, सीटू के हस्तक्षेप और डीसी के घेराव के बाद प्रशासन को इन मजदूर साथियों को रिहा करना पड़ा।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के कपड़ा उद्योग में 1982 से ही ठेका प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर रखा है। लेकिन, मालिकान ने ईएसआइ और पीएफ के फर्जी रजिस्टर बना रखे हैं और अपने चहेतों के नाम दर्ज करके गैरकानूनी ढंग से ठेका प्रथा को चला रहे हैं। पानीपत के किसी भी उद्योग में न मजदूरों के नाम दर्ज किए जाते हैं और न ही हाजिरी कार्ड और वेतन स्लिप दी जाती है। इसके साथ ही मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी पूरा नहीं दिया जाता।

लिहाजा, सीटू ने सभी मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज करवाने, वेतन स्लिप व हाजिरी कार्ड दिलवाने, न्यूनतम वेतन लागू करवाने, महिला मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन दिलवाने संबंधी मांगपत्र अलग-अलग सभी फैक्टरियों के प्रबंधकों/मालिकान को दिए थे। इसके अलावा, हड़ताल की अवधि के दौरान हर रोज श्रम विभाग और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों पर जनसभाएं और जल्से-जुलूस आयोजित किए गए।

इसी क्रम में 6 जून को नौवें दिन भी स्पिनिंग मिल के मजदूरों की हड़ताल जारी रही। इस मौके पर हाली पार्क में हुई मजदूरों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के नेता सुनील दत्त ने बताया कि 5 जून को हुई वार्ता मिल मालिकों के अड़ियल रुख के चलते विफल हो गई है और अगली वार्ता आज होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल मालिकान और श्रम विभाग के अधिकारी आपस में मिलीभगत करके मजदूरों का शोषण कर रहे हैं।

यूनियन के अध्यक्ष जयभगवान ने उपर्युक्त मांगों को लेकर हड़ताल को जारी रखने का एलान किया। यूनियन के सचिव एसए ख़ां ने समझौता वार्ता के विफल होने की सूरत में उपायुक्त कार्यालय का घेराव और भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह श्रम विभाग को फैक्टरी मालिकान की तरफदारी करने के बजाय श्रम कानून लागू करवाने का निर्देश दे। उन्होंने मजदूरों से भी अपील की कि बड़ी संख्या में हाली पार्क में आयोजित रैली में शामिल हों। एसएफआइ राज्य महासचिव जयभगवान ने मजदूरों के संघर्ष का समर्थन किया।

इससे पहले जेल से रिहा होकर जुलूस के साथ पार्क में पहुंचे यूनियन के नेता सुभाष का फूलमालाओं से स्वागत किया गया और प्रबंधकों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस दिन भी उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया।

पानीपत के स्पिनिंग मिल मजदूरों के संघर्ष का यही जज्बा था, जिसने प्रशासन को हस्तक्षेप करने और मालिकान को मजदूरों के पक्ष में समझौता करने पर मजबूर कर दिया। □

रोहतक में विशाल रैली

सीटू से संबद्धित हरियाणा की आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन ने रोहतक में 13 मई 2006 को एक विशाल रेली आयोजित की। फरीदाबाद, मेवाट, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, जिंद, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद एवं झज्जर से 2000 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारी राज्य में 50 से अधिक परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व कर रैली में भाग ले रहे थे, जिसकी अध्यक्षता फरीदाबाद से देवेंद्री शर्मा ने की। भिवानी से कमलेश सांगवान ने कार्यवाही का संचालन किया। आयोजक कमेटी की संयोजिका रतनेश ने ज्ञापन प्रस्तुत किया जोकि मुख्य मंत्री को देने के लिए था। आइफा की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा, सचिव हरगोविंद कौर तथा कार्यकारिणी कमेटी की सदस्या ऊषा रानी ने भीड़ को संबोधित किया जिसमें सीटू राज्य कमेटी के महासचिव सतवीर सिंह एवं सचिव वीरेन्द्र मलिक तथा राज्य सरकार कर्मचारियों की सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव आर सी जग्गा भी भीड़ को संबोधित किया। रैली में विभिन्न जिलों के आंगनवाड़ी कर्मचारी भी बोले।

नीलिमा मैत्रा ने बताया कि देश के एक तिहाई बच्चे अल्प पोषित हैं। उन्होने आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने तथा मजबूत करने तथा आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के काम करने व रहने के स्तरों को निचले स्तर से सुधारने के लिए कदम न उठाने पर सरकार की निन्दा की। उन्होने मांग की कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रेड 3 व सहायिकाओं को ग्रेड 4 के सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करो। उन्होने सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जेसे भविष्यनिधि एवं पेंशन देने की भी मांग की। रैली में वीरेन्द्र तथा सतवीर ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों का उनकी एकता को बचाने एवं उनकी एकता को तोडने के प्रयत्न कर रहे दबावों के आगे न झुकने का अहवान किया। उन्होने सीटू राज्य कमेटी द्वारा उनके राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने के लिए किए गए प्रयत्नों का वर्णन किया। भीड़ को सरोज वशिष्ठ की याद दिलाकर यह विश्वास दिलाया गया कि सीटू राज्य कमेटी सरोज वशिष्ठ द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों को पूरा करेगी। जग्गा ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को एकजुट होकर कार्य करने तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए कहा तथा सर्व कर्मचारी संघ द्वारा हर प्रकार की सहायता तथा समर्थन का विश्वास दिलाया।

बैठक में अगले दो माहों में सभी जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा फैडरेशन के आहवान पर संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में विशाल भूख हड़ताल में बड़े स्तर पर लामबंद करने का भी निर्णय लिया गया। □

पृष्ठ 10 का शेष

इसमें भाग लिया। सीटू से अरूण मेहता ने भागीदारों का स्वागत किया तथा जिले में सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने का आहवान किया।

हेमलता ने फैडरेशन की मांगों का वर्णन कर उन्हें स्पष्ट किया। उन्होने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण करना तथा मजबूत करना इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे बच्चों को भोजन, शिक्षा तथा पोषण ठीक प्रकार से मिलेगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध करवाकर जोकि हमारे बच्चों का अच्छे भविष्य बनाने में सहायक हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु उनकी सेवाओं को नियमित करने के स्थान पर सरकार उन पर ध्यान ही नही दे रही है। उन्होने सूचना दी कि 18 से अधिक राज्यों गें आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 18 अप्रैल को इन मागों पर फ़ैडरेशन के नेतृत्व में प्रदर्शन किए। फैडरेशन जुलाई 2006 में संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने एक विशाल भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्होने भागीदारों को भावनगर में संगठन को मजबूत बनाने तथा उनकी मांगों के लिए लड़ने की सलाह दी। शुभा शमीम महाराष्ट्र में अपने अनुभवों के बारे में बोलीं, जहां आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने संघर्षों से राज्य सरकार से कुछ वादे करवाने में सफल हुईं।राज्य सरकार ने पेशन का वादा किया परन्तु उस पर अभी तक कोई अमल नही किया गया है। वे वादों का पालन करवाने तक अपने संघर्ष को जारी रखेंगे।

एडवा से जयश्री बेन तथा जिले (सीटू) से अशोक सोमपुरा ने भागीदारों को बधाई दी तथा अपने संगठनों की ओर से हर प्रकार के समर्थन एवं सहायता का विश्वास दिलाया। बैठक में स्थानीय समस्याओं पर जिला अधिकारियों को रिप्रेज़ेन्टेशन देने तथा शीघ्र ही जिला स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया।

यूनियन के कार्यकर्ताओं की एक अन्य बैठक अहमदाबाद में गुजरात राज्य कमेटी सीटू के दफ्तर में 14 मई को हुई। बैठक में अहमदाबाद, भावनगर तथा जूनागढ़ के यूनियन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहां सीटू राज्य कमेटी के सह सचिव अरूण मेहता भी उपस्थित थे। बैठक में एक राज्य स्तरीय आयोजक कमेटी का गठन किया गया जिसमें अहमदाबाद, भावनगर, जुनागढ़ तथा सबरकांता में कार्य आरम्भ करने फैसला किया गया। परियोजना स्तर पर बैठकें आयोजित करने, सदस्य बनाने तथा सितम्बर के अंत तक जिला अधिवेशन करने एवं इस वर्ष के अंत तक एक राज्य स्तरीय अधिवेशन करने का निर्णय लिया गया।

16 मई को चंदू भाई लखानी के साथ एक बैठक की गई। चंदू भाई लखानी गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं जो कि एक स्वतंत्र यूनियन है तथा मोदी सरकार की कम्यूनल एवं आंगनवाड़ी कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरूद्ध कार्य करती है तथा उन्होने आइफा के नेताओं को विचार के लिए आमंत्रित किया। बहस में हेमलता, शुभा एवं अरूण मेहता ने भाग लिया जिसमें लखानी ने उनकी यूनियन को आइफा से संबद्धित करने तथा गुजरात में सीटू से संबद्धित यूनियनों के साथ कार्य करने मंशा जताई। □

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों का बढ़ता संघर्ष

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों के अग्रणी व लड़ाकू संगठन ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में गत माह थर्मल, पानीपत के चीफ इंजीनियर के कार्यालय पर धरना आयोजित कर निगम प्रशासन के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किया गया। राज्य के तीनों बिजली-उत्पादन केंद्रों (पानीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद) के कर्मचारियों की लंबे अर्से से लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के प्रति हरियाणा विद्युत-उत्पादन निगम (एचपीजीसी) प्रशासन के उदासीनतापूर्ण रवैए के विरोध में यह कार्रवाई आयोजित की गई। यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस विरोध कार्रवाई में हाइडल यमुनानगर, थर्मल फरीदाबाद और थर्मल पानीपत के कर्मियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

धरने पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एचपीजीसी प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर एक माह के अंदर प्रोजेक्ट के कर्मियों की मांगों व समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो यूनियन पंचकूला स्थित मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। थर्मल यूनिट अध्यक्ष जगपाल सिंह सांगवान ने मंच संचालन किया। अंत में चीफ इंजीनियर को प्रबंध निदेशिका के नाम ज्ञापन दिया गया।

बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगें हैं: पर्सनल पोस्टों पर कार्यरत कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिया जाए; यूनियन की मांग के अनुरूप उत्पादन लाभांश की नीति को संशोधित किया जाए; वर्क लोड के अनुसार नए पदों का सृजन किया जाए और स्थायी भर्ती कर रिक्त पड़े पदों को भरा जाए; सभी प्रकार के भत्ते संशोधित किए जाएं; मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए; तरक्की भर्ती नीति में संशोधन करके टेक्नीशियन-2 के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए; मैट्रिक, आइटीआइ कर्मियों को वरीयता दी जाए; डेली वेजिज वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन लाभ में जोड़ा जाए; यूनिट 7 और 8 में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए; थर्मल की आवासीय कॉलोनी में 500 नए मकानों का निर्माण कराया जाए; निजीकरण, ठेका प्रथा की नीतियों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए; और, सभी कर्मचारियों को दीवाली का बोनस दिया जाए।

इस विशाल धरने को संबोधित करते हुए देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि 17 जनवरी, 2006 को एचपीजीसी की प्रबंध निदेशिका श्रीमती ज्योति अरोड़ा आइएएस के कार्यालय में यूनियन की वार्ता समिति के प्रतिनिधियों की अजेंडा बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगों को लागू करने के बारे में सहमति बनी थी। लेकिन, इस सहमति पर आज तक अमल नहीं हुआ। इसके विरोध में 12 अप्रैल, 2006 को यूनियन के महासचिव सुभाष लांबा के हस्ताक्षर से नोटिस भेजकर निगम की प्रबंध निदेशिका से स्वीकृत मांगों को लागू करने का अनुरोध किया गया और 16 मई, 2006 के धरने की चेतावनी दी गई। लेकिन, एचपीजीसी प्रशासन ने स्वीकृत मांगों को लागू करना तो दूर, नोटिस का जवाब तक देना उचित नहीं समझा। इसी संवादहीनता के कारण बिजली कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर हैं।

सुभाष लांबा ने कहा कि राज्य में सरकार बदली है, लेकिन पिछली चौटाला सरकार की जनविरोधी-कर्मचारीविरोधी नीतियों को पलटा नहीं गया है। मजदूरों और कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं और उनके आंदोलनों में पुलिस का दखल बढ़ रहा है। आइटीआइ को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। बिजली-उत्पादन बढ़ाने की जनता की प्रमुख मांग की तरफ राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जबकि पूरे राज्य में गंभीर बिजली संकट बना हुआ है और रास्ते जाम कर जनता अपना विरोध प्रकट कर रही है। बिजलीकर्मियों की प्रमुख मांगों को लागू करवाने के लिए यूनियन 26 मार्च, 2006 को रोहतक में विशाल रैली आयोजित कर चुकी है।

साझा मांगों के लिए संयुक्त संघर्ष चलाने की नीति का जोरदार समर्थन करते हुए सुभाष लांबा ने बिजली कर्मचारियों के अन्य सभी संगठनों से एकजुट होकर संघर्ष तेज करने की अपील की और 28 मई को पानीपत में सीटू की मजदूर अधिकार रैली में बढ़-चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया। उपस्थित कर्मचारियों ने हाथ उठाकर गगनभेदी नारों के साथ इसका समर्थन किया।

धरने को मुख्य संगठनकर्ता सतबीर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनार्दन कोठारी, सीटू राज्य महासचिव सतबीर सिंह, वित्त सचिव यादराम, धर्मवीर मलिक, मंगल सिंह, जितेंद्र तेवतिया, रणवीर देशवाल, शिवराम, रत्तीराम, वेदप्रकाश यादव, प्रेमराज, सुखबीर, सुरेश मिश्र, ज्ञानचंद, जयप्रकाश, सतपाल सैनी, एनपी सिंह, राजपाल सिक्का, नरेश, विनोद त्यागी आदि ने भी संबोधित किया।

धरने के बाद राज्य कमेटी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात करके मांगों का ज्ञापन सौंपा। उधर विद्युत कानून-2003 की आड़ में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को 9 जून से पहले भंग करने के खिलाफ पंजाब के बिजली कर्मचारियों की 8 जून की हड़ताल के समर्थन में भी 2 जून, 2006 को पूरे हरियाणा में सर्कल स्तर पर प्रदर्शन किए गए। इस मौके पर बिजली कर्मचारियों ने राज्य के सभी अभियंता कार्यालयों पर 5 से 7 जून तक भूख हड़ताल करने और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। ☐

पृष्ठ 2 का शेष

सम्बोधित किया। सीआइटीयू की बिहार राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड चण्डी प्रसाद तथा बेफी बिहार के महासचिव कामरेड बी0 प्रसाद ने संयुक्त रूप से सभा की अध्यक्षता की। गांधी मैदान के पास सभी वामपक्षी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा कर्मचारी संघों की ओर से एक रंगारंग जुलूस निकाला गया जो रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंच कर जन सभा में बदल गया। सीआइटीयू, एटक, यूटीयूसी, यूटीयूसी-एलएस, टीयूसीसी के राज्य नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। सीपीआइ (एम) के राज्य सचिव कामरेड विजयकांत ठाकुर तथा कामरेड सर्वोदय शर्मा विशिष्ट अतिथि थे। सायंकाल पटना रेलवे पार्सल मजदूरों की एक सभा का आयोजन किया गया जिसे कामरेड अरुण कुमार मिश्र और अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया।

मध्य प्रदेश : ग्वालियर में ग्वालियर युनाइटेड काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन्स (गुक्टू) के झण्डे तले मई दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीआइटीयू के लश्कर व हजीरा कार्यालयों और गुक्टू के लोकोशेड आफिस के साथ ही असंगठित मजदूरों ने बाड़ा, हजीरा, नयी सड़क, शिंदे की छावनी, नाका चन्द्रवदनी, पड़ाव व इन्द्रगंज के अपने कार्यस्थलों पर झण्डे फहराए। गुक्टू के संयोजक बी पी सोनिया, सीआइटीयू की राज्य समिति के सचिव रामविलास गोस्वामी, बीएसएनएल कर्मचारियों के नेता अतिराम सिंह व एम पी त्रिपाठी एवं रेलवे के बी एस कंसाना इत्यादि नेता इन आयोजनों में शामिल हुए। गुक्टू के महासचिव एम के जायसवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्वालियर में संयुक्त रैली व जुलूस निकाला गया और महाराज बाड़े पर जन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के मुख्य वक्ता सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव कामरेड बादल सरोज थे। उनके अतिरिक्त जीडीआईईए की डबरा, दतिया, नगर शाखा एक-दो, तीन, चार, मुरार, मुरैना, शिवपुरी, गोहद, भिंड, श्योपुर, गुना, राधौगढ़, अशोक नगर सहित मण्डल कार्यालय में भी द्वार प्रदर्शन कर मई दिवस मनाया गया। ☐

रीवा : आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का जिला सम्मेलन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन (सीटू) का जिला सम्मेलन मध्य प्रदेश में रीवा में 2 अप्रैल 2006 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में जिले भर से लगभग 300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने भाग लिया।

संगठन की जिला अध्यक्ष सावित्री शुक्ला ने झंडारोहण किया तथा अध्यक्ष मंडल सहित अध्यक्षता की। शहीदों को श्रद्धांजली देकर कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सम्मेलन का उद्घाटन यूनियन की प्रदेश महासचिव किशकरी वर्मा ने किया। उन्होने अपने वक्तव्य में संगठन को मजबूत करने एवं इसे गांव के कोने–कोने तक पहुंचाने की बात कही साथ ही हितग्राही व उनके माता पिता व क्षेत्र के लोगों के बीच

कार्यकर्ता व सहायिकाओं को अच्छे संबंध बनाने की सलाह दी। रोजमर्रा की उनकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कराकर उनके बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की बात कही। उन्होने यह भी कहा कि हमे अपने क्षेत्र के हितग्राहियों के बीच अपनी समसयाओं और उनके लिए हो रहे आंदोलनों से भी अवगत कराना चाहिए और उनकी समस्याओं को भी अपनी मांगो के साथ जोड़कर उन्हें भी अपने आंदोलन से जोड़ना चाहिए। तब हमारा संगठन मजबूत होगा अपनी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होंगें।

सम्मेलन की मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा जनवादी महिला समिति की प्रदेशाध्यक्ष संध्या शैली ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमे डरे बिना संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि आज हमें इतने काम सौंपे जाते है परन्तु सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी नही लेती, उन्हाने कुपोषण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एक गांव से दूसरे गांव घर–घर वजन करने जाती हैं, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि कई बार ऐसे कामो में हमारी साथियों के साथ दुर्घटना हो जाती है, उन्होने पर्यवेक्षक शकुंतला वर्मा के हाथ काटे जाने का जिक्र करते हुए बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकांरी ड्यूटी करते हुए उसके हाथ काट दिए गए और जब दुर्घटना उसके साथ घटी तो सरकार ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया, पर जब आंगनवाड़ी संगठन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने उसमें हस्तक्षेप किया तब जाकर उसे कुछ राहत मिली। इसलिए हम सब को संगठन बनाकर मजबूती के साथ अपनी सुरक्षा की मांग के लिए भी लड़ने की जरूरत है।

संगठन की जिला महासचिव फूलवसी नामदेव ने संगठन की लिखित रिपोर्ट सभी के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर बहस में 10 लोगो ने भाग लिया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से 27 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई, जिसकी अध्यक्ष सावित्री शुक्ला, उपाध्यक्ष बदरूनिस्सा खान, पुष्पा वर्मा (सहायिका), कोषाध्यक्ष छाया वर्मा,महासचिव मूलवसी नामदेव, सचिव शशिकला पांडे, सरोज मिश्रा चुनी गई।

सम्मेलन का समापन सटू के जिला महासचिव विद्या शंकर मुफलिस ने किया। उन्होने अपने वक्तव्य में कहा कि जो आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्या है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाकर देशभर में पूरक पोषण आहार प्रत्येक केंद्र को उपलब्ध कराने, आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने। उक्त मांग लम्बित रहने तक मानदेय बढ़ाकर कार्यकर्ताओं को 3000रू मासिक तथा सहायिकाओं को 2500रू मासिक देने, मूल्य सूचकांक से जोड़ने कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने, भविष्य निधि, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, ग्रीष्मकालीन अवकाश देने आदि मांगों का सीटू समर्थन करती है। जनविरोधी नीतियों एवं महिलाओं के ऊपर जिस तरह पूरे प्रदेश में अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ महिलाओं को आगे आने एव संघर्ष तेज करने की आवश्यकता है।

सम्मेलन के समापन की घोषणा शशिकला पाण्डे ने जोशीले नारों के साथ की। □

पृष्ठ 16 का शेष

2001 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि देश के सभी जनआवासों में सक्रिय आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए, सभी स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों को तुरन्त चालू किया जाएगा तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 14 लाख से बढ़ाई जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने देश में मानव विकास से संबंधित सूचियों में सुधार के निर्देश दिए हैं।

यूपीए सरकार ने भी एनसीएमपी में यह प्रतिबद्धता ली कि प्रत्येक जनआवासों में खोलकर आईसीडीएस को व्यापक बनाने के लिए सभी जनआवासों में सक्रिय आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध कराए जाऐंगें तथा इसमें सभी बच्चों को पूर्णरूप से कवर करना सुनिश्चित किया जाएगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अल्पावधि सामाजिक कार्यकर्ता कहकर, जोकि उनके काम का सही रूप प्रदर्शित नही करता, उन्हें सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने से इन्कार किया जाता है। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नई भर्ती का अनुपात निश्चित करती है। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बजट में प्रोविजन बनाती है, जिसे बहकावे के रूप में मानदेय कहा जाता है। सरकार सर्कल स्तर पर आईसीडीएस सुपरवाईज़रों सहित सुपरवाइज़री मैकेनिज़म की व्यवस्था करती हैं। परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कार्य की देखरेख की जाती है तथा किसी अल्पसमय में अनुशासनात्मक रूप से कदम उठाए जाते हैं। इसके सभी अफसर सरकारी कर्मचारी हैं, परन्तु निम्न स्तर से अहम भूमिका निभाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आईसीडीएस को लागू करने के लिए साधन है तथा उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने से इन्कार किया जाता है, जोकि इन महिलाओं के साथ घोर अन्याय है।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भुगतान किया जाने वाला मानदेय इतना कम है कि उससे किसी भी परिवार की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है। जब सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वेतन भुगतान करने का कोई प्रबंध नही है, वे भूखों मरने के लिए बाधित हैं।बहुत सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जोकि 20–25 वर्षों से कार्य कर रहीं हैं तथा उनकी उम्र 58 वर्ष हो गई है, उन्हें बिना किसी पेंशन या क्षतिपूर्ति के सेवानिवृत्त किया जा रहा है। क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों की सेवा करते हुए आईसीडीएस में दशकों तक कार्य करने के बाद भी उनकी वृद्धावस्था के लिए उनके पास कुछ नही बचता।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अल्प अवधि के कार्यकर्ता कहना गलत है क्योंकि अनुभव में है कि वे राज्य सरकार द्वारा उनके विश्वास पर छोड़े गए विभिन्न कार्यों जैसे ओआरएस के बारे में जागरूकता फेलाना, अपर रेस्टीरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस के लिए सीधे निरीक्षण चिकित्सा प्रणाली, एड्स जागरूकता, जन्म नियंत्रण के तरीकों के लिए प्रोरणा और शिक्षा इत्यादी, शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य जैसे पूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, डीपीईपी अनौपचारिक शिक्षा इत्यादी को पूरा करने के लिए 7 घंटे से अधिक कार्य करतीं हैं। कुछ राज्यों में वे छोटी बचतों को बढ़ाने, स्वयं सहायता समूह बनाने, बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण, कुष्ठ रोग सर्वेक्षण, हाथी पांव बीमारी सर्वेक्षण, पशु गणना इत्यादी कार्यों में भी शामिल हैं। संक्षेप में, आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के पालन एवं जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किए गए केंद्र के रूप में होता है। कुछ राज्यों में उन्हें दहेज व बाल विवाह के विरूद्ध अभियान चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। परन्तु उन्हें न्यूनतम मजदूरी के समान भी भुगतान नही किया जाता। बहुत से राज्य अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन का भुगतान नही करते, और जहां अतिरिक्त वेतन दिया भी जाता है, बहुत कम है।

इसी संबंध में राज्य सभा की पैटिशन कमेटी ने निरीक्षण किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निश्चित रूप से न्यूनतम मजदूरी के समान वेतन मिलना चाहिए, मुख्य रूप से तब जब उनके काम का बोझ बहुत बढ़ जाए तथा राज्य सरकार उनकी सेवाओं का उपयोग करे। राज्य सभा की पैटिशन कमेटी के इस निरीक्षण को गम्भीरता से विचार किए जाने तथा व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। आईसीडीएस के भुगतान की समीक्षा के अन्तर्गत भोजन के अधिकार, हमारे देश के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आईसीडीएस के अन्तर्गत विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों को तुरन्त माना जाए।

पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सरकार द्वारा उनकी सही मांगों को अनदेखा कर देने पर संघर्षरत हुई तथा उन्होनें संसद के मानसून सत्र के दौरान दस दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। पूरे देश से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भूख हड़ताल में भाग लेंगी तथा सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर खींचने का प्रयत्न करेंगी।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन मागों पर गम्भीरता से विचार करें तथा हजारों निर्धन महिलाओं जोकि इस आशा के साथ आई है कि सरकार उनकी मांगो पर ध्यान से विचार करेगी, को निराश न करके उनके पक्ष में कुछ सकारात्मक घोषणा करने का अनुरोध करते है।

धन्यवाद,

प्रार्थी

नीलिमा मैत्रा	ए आर सिंधु	हरगोविंद कौर	हेमलता
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	महासचिव

अखिल भारतीय आंगनवाडी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन

बी टी आर भवन, 13 ए, राउज एवेन्यू, नयी दिल्ली–110002
फोन 2322 1288, 2322 1306 फैक्स–2322 1284

6 जुलाई 2006

सेवा में,

श्रीमति रेणुका चौधरी
माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली– 100011

विषयः– आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मुख्य मांगें

महोदया,

इस वर्ष फरवरी में सांसद डॉ एम बाबू राव तथा हमारी महासचिव के हेमलता के साथ आपकी एक बैठक हुई। कृप्या इस बैठक का पुनः आह्वान करें। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं की मांगों की सुनवाई तथा उन पर सहानुभूति से देखरेख करने का भरोसा दिलाने के लिए आपका धन्यवाद अदा करते हैं।

परन्तु जैसा कि दुर्भाग्यवश नोट किया गया कि उस बैठक के चार माह पश्चात् भी उनकी मांगों पर ठोस रूप से कोई कदम नही उठाया गया है। आपकी जांच के लिए हम नीचे कुछ मुख्य मांगों को हाइलाइट कर रहे हैं।

- ❖ आईसीडीएस को स्थाई बनाया जाए और सभी बस्तियों में एक निश्चित समय सीमा के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएं।
- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेड 3 और सहायिकाओं को ग्रेड 4 कर्मचारियों के रूप में नियमित करो और उन्हें सभी सेवा लाभ दो।

इसके लम्बित रहते हुए

- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढाकर 3000रू तथा सेविकाओं का 2000रू प्रतिमाह दिया जाए।
- ❖ मानदेय को उपभोक्ता सूचकांक के साथ जोड़ा जाए
- ❖ 60 वर्ष से अधिक उम्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक लाख रूपए तथा सहायिकाओं के लिए पचास हजार रूपए का एकमुश्त एक्स ग्रेशिया लाभ तय करें।
- ❖ 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर पेंशन
- ❖ सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ईपीएफ तथा इएसआई कानूनों के अन्तर्गत लाया जाए।
- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय स्तर की त्रिपक्षिय कमेटी का गठन करो जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

हमारी उपरोक्त मांगें न्याय संगत हैं; इसके पक्ष में हम आपके समक्ष निम्नलिखित तर्क रखते हैं।

30 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आईसीडीएस केवल एक योजना के रूप में ही कार्य कर रहा है तथा आईसीडीएस के निचले स्तर से कार्य करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को सरकार की ओर से कर्मचारी के रूप में पंजीकृत भी नही किया गया है। उन्हें बहुत ही कम मानदेय का भुगतान किया जाता है। उन्हें कोई रोजगार सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नही है। दशकों तक सेवा के बाद भी उनकी वृद्धावस्था के लिए कुछ नही बचता है और वे भूखो मरने के लिए बाध्य हैं। उनके लिए पदोन्नति के भी अवसर नही है।

हाल ही के एनआईपीपीईई के अध्ययनों सहित बहुत सी ऐजेन्सियों के अध्ययनों पर आपके मंत्रालय द्वारा आयोग बैठाया गया, आईसीडीएस के तीन दशकों के अप्रेज़ पर आयोग ने बच्चों में कुपोषण की बहुत सी घटनाओं को कम करने, इम्यूनाइज़ेशन कवरेज बढ़ाने, बच्चों की वृद्धि की देखरेख करने, विद्यालय पूर्व की शिक्षा उपलब्ध कराने महिलाओं को पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने में आईसीडीएस की सकारात्मक भूमिका स्थापित करता है। बाल देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराकर भी आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण कामकाजी महिला की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परन्तु यद्यपि आईसीडीएस पिछले 30 वर्षों में फैला है, फिर भी यह केवल देश में छः वर्ष तक के बच्चों का केवल एक तिहाई भाग कवर कर पाया है।

पृष्ठ 15 पर

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए–13, राऊस एवेन्यू नई दिल्ली–2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित।